बाढ़ पीड़ितों का भोजन समाजसेवा के भरोसे

राशन किट और पका हुआ भोजन दे रहे समाजसेवी और संस्थाएं, नाम हो रहा प्रशासन का

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) यमुना नदी में आई बाढ़ से कल्याणकारी सरकार और उसके प्रशासिनक अधिकारियों की बेशर्मी उजागर हो गई। प्रशासनिक अधिकारी संकट आने तक केवल बैठक कर बाढ़ से बचने की कागजी रणनीतियां बनाते रहे और बाढ़ आने पर सांसद, विधायक और मंत्री फोटो सेशन कराने में मस्त नजर आए। बाढ़ पीड़ितों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ी। प्रशासन ने तो पीड़ितों के भोजन पानी का भी इंतजाम नहीं किया। जिले के समाजसेवियों और समाजसेवी संस्थाओं ने यह जिम्मा संभाला, हालांकि इसका श्रेय प्रशासन लेता रहा। बहुत संभव है कि जैसे कोरोना काल में समाजसेविसों से दान में मिली राशन किट 'खरीदी गई' दिखा कर लाखों रुपये की बंदरबांट की गई उसी तरह बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राशन किट और पके भोजन का भी बिल लगा कर फिर से लूट कमाई की जाए।

जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने का इंतजाम करने का जिम्मा रेड क्रॉस सोसायटी को सौंपा है। कोरोना संकट में ऑक्सीजन घोटाला करने और संस्थाओं से दान में मिलीं राशन किटों में हेराफेरी करने के दागी विमल खंडेलवाल ने बाढ़ की इस आपदा में फिर से लूट कमाई का अवसर देखते हुए जिला उपायुक्त और रेड क्रॉस सोसायटी के चेयरमैन विक्रम सिंह से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इधर, सोसायटी के पदाधिकारी राशन किट या पका हुआ भोजन खरीद कर बाढ़ पीड़ितों को देने से कतरा रहे हैं। एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बाढ़ राहत सामग्री का भुगतान नहीं किया जाता।

बीते अनुभव बताते हुए कहा कि बिलों पर इतनी आपत्तियां लगा दी जाती हैं कि बेहतर है कि खरीद ही नहीं की जाए। ऐसे में सोसायटी समाजसेवी संस्थाओं, उद्यमियों और समाजसेवियों के आगे हाथ फैला रही है। सोसायटी के सचिव विजेंद्र सौरोत के मुताबिक दस हजार राशन किट बंटवाने का लक्ष्य रखा गया है। सोसायटी के पदाधिकारी बताते हैं कि एसडीएम भी उन पर राशन किट उपलब्ध कराने का दबाव बना रहे हैं। शहर की लायंस क्लब, सेक्टर 15 की आरडब्ल्यूए सहित कई समाजसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों से सात हजार के करीब राशन किट मिलनी हैं बाकी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेहनत रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारी कर रहे हैं और श्रेय दागी विमल खंडेलवाल ले रहा है। सोसायटी के राज्य कमेटी के सदस्य मनोज बंसल भी समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं से बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रतिदिन 500 से 800 लंच पैकेट दान करवाते हैं। दागी विमल खंडेलवाल ने डीसी के सामने इसका श्रेय लिया तो आहत होकर मनोज बंसल ने रेडक्रॉस सोयायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों का वाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। सोसायटी के अन्य पदाधिकारियों में भी विमल खंडेलवाल की कारगुजारियों से गुस्सा है। इन लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन घोटाले के जिम्मेदार विमल खंडेलवाल के कारण सोसायटी की छवि धूमिल हो रही है वह डीसी के करीबी होने और सोसायटी का पदाधिकारी होने के नाम पर दानदाताओं और संस्थाओं को वरगला रहा है।

खाद्य सामग्री बांटे मदर टेरेसा सर्विस क्लब और श्रेय लूटे जिला प्रशासन

सिर्फ मॉक ड्रिल पर खर्च करने के लिए है आपदा प्रबंधन का बजट

यमुना नदी में बाढ़ आने से हजारों घर और परिवार बर्बाद हो गए और प्रशासन का आपदा प्रबंधन सिस्टम पूरी तरह सक्रिय ही नहीं हुआ। रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारी कहते हैं कि इतना बड़ा बजट होने के बावजूद प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को भोजन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा जबकि आपदा प्रबंधन में पीड़ितों के बचाव, अस्थायी आवास, भोजन, इलाज आदि सुविधाएं देने के लिए भारी भरकम बजट है। सच्चाई ये है कि बाढ़ आने पर प्रशासन और उसका आपदा प्रबंधन तंत्र पीड़ितों तक बाद में पहुंचा इससे पहले लोगों ने अपने ट्रैक्टर, वाहन, नावें लगाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की। सवाल ये है कि आपदा प्रबंधन का बजट जब बाढ़ पीड़ितों को राहत, भोजन पानी, दवाएं उपलब्ध कराने पर नहीं खर्च किया जाएगा तो कब किया जाएगा। लगता है कि आपदा प्रबंधन सिस्टम और उसका बजट गाहे

बगाहे सेक्टर 12 लघु सचिवालय में मॉक ड्रिल करने के लिए ही बना है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि आपदा प्रबंधन के पास तो कोई टीम है ही नहीं तो काम का क्या खाक किया जाएगा। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रेडक्रॉस और एनडीआरएफ, पुलिस की टीमों ने ही राहत और बचाव कार्य किए।

बेशर्म सांसद, विधायक मंत्रियों ने सिर्फ लफ्फाजी की

यमुना नदी में आई बाढ़ जैसे सांसद, विधायक मंत्रियों के लिए इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम साबित हुई। बाकायदा पीआरओ, कैमरामैन की टीम और प्रशासनिक सूचना तंत्र के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच कर इन जन प्रतिनिधयों ने जनता से उसका हालचाल पूछने का ड्रामा किया। बीते दिनों प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा मंझावली में अपनी पीआरओ टीम के साथ बाढ़ पीड़ितों का हाल लेने पहुंचे। अव्यवस्था से बिलबिला रहे पीड़ितों से मंत्री मूलचंद शर्मा ने ऐसे कुशलक्षेम पूछा जैसे उनके लिए सरकार और प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए हों। परेशानी से जूझ रहे लोगों ने मंत्री को खरी खरी सुना दी कि खाना पानी तो छोड़ दो जब से बाढ़ आई है ग्राम प्रधान गायब हो गया है, हम लोग जिंदा हैं कि मर गए, हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई या कुछ बचा है, ढोर-डंगरों के चारे की क्या व्यवस्था है ग्राम प्रधान कुछ भी पूछने नहीं आया। लोगों की परेशानी देख उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोई ठोस बात कहे बिना मंत्री जी चलते बने। सांसद किशनपाल गूजर ने भी बाढ़ पीड़ित बसंतपुर, मोहना, मोठुका बागपुर सहित अन्य बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर फोटो सेशन करवाया। लोगों की समस्या सुनने और उनका समाधान करने की औपचारिकता की। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों का कहना था कि जिन्हें हमने अपने वोट से सांसद और विधायक बनाया वह आज हमारे प्रतिनिधि की तरह नहीं शासक की तरह आकर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, यदि बाढ़ पीड़ितों की इतनी ही परवाह है तो अपनी निधि से इलाके के लिए कुछ ठोस कार्य कराएं ताकि बाढ़ की समस्या में हमें इतनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

धर्म-जाति देख कर बांटी राहत सामग्री

भाजपाई चालबाज राजनीतिज्ञ समाज को धर्म, जाति आदि के नाम पर बांटने में जुटे हुए हैं। उनकी ये चाल 'समाजसेवा' में भी सामने आ रही है। बाढ़ पीड़ितों को समाजसेवी संस्थाएं भी खाद्य सामग्री बांटने में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करती नजर आईं। बसंतपुर में बीते शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। सवर्णों और अधिसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन बांटा गया जबकि अल्पसंख्यक और दलित बस्तियों तक भोजन पहुंच ही नहीं पाया। यदि इन बस्तियों के लोग भोजन मांगने पहुंचते तो उन्हें भोजन के नाम पर एक कटोरी खिचड़ी पकड़ा दी जाती।

बसंतपुर की रेशमा का कहना था कि दो दिन में कोई राशन किट तो मिली नहीं खाना भी इतना कम देते हैं कि आदमी उसे खाने के बावजूद भूखा ही रह जाता है। परिवार के सदस्यों को बांटें तो चंद दाने ही आते हैं। दलित और अल्पसंख्यक बस्तियों में अधिकतर परिवारों को पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण भूख से बिलबिलाते हुए देखा गया।

घोटालों-हेराफेरी का गढ़ बन गई रेडक्रॉस सोसायटी

रसीद घोटाले के आरोपी जितिन शर्मा को नियम ताक पर रख दी गई पदोन्नति

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जिला रेडक्रॉस सोसायटी घोटोलों, हेरोफेरी और पदाधिकारियों की स्वेच्छाचारिता का गढ़ बन चुकी है। कोरोना काल में रिकॉर्ड बिना ही ऑक्सीजन सिलिंडर, राशन किट में घोटाला किया गया और फिर क्लर्क जितिन शर्मा को भी नियम-कानून ताक पर रख कर पदोन्नत कर दिया गया। मज़दूर मोर्चा अखबार ने जितिन शर्मा द्वारा 60 हजार रुपये की हेराफेरी करने की खबर छापी तो अब अधिकारी उसे बचाने में जुटे हैं।

किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या पंजीकृत संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति के नियम कायदे होते हैं। कर्मचारी की पदोन्नति के लिए उसकी वार्षिक गोपनीय रपट (एसीआर) का साफ सुथरा होना और पेपर अंडर कंसीडरेशन (पीयूसी) होना अनिवार्य हैं। रेड क्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों ने साठ हजार रुपये गबन के आरोपी जितिन शर्मा को पदोन्नति देने के लिए उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और पीयूसी ही गायब कर दीं। कोरोना संकट काल में हुए इस खेल का खुलासा नहीं होता यदि आरटीआई से इसकी जानकारी न मांगी जाती।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी में लिपिक पद पर तैनात जितिन शर्मा को सेंट जॉंस एंबुलेंस (इंडिया) हरियाणा राज्य शाखा की ओर से 28 फरवरी 2022 को जिला प्रशिक्षण अधिकारी (डीटीओ) पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति का कारण उसका फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग (विषय) का योग्य प्रवक्ता होना बताया गया।

आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला ने जब इस संबंध में जानकारी मांगी तो पदोन्नति में किया गया खेल सामने आया। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि लिपिक जितिन शर्मा की एसीआर और पेपर अंडर कंसीडरेशन (पीयूसी) गायब हैं। एसीआर में कर्मचारी के साल में किए

जितिन शर्मा

गए कार्य के आधार पर रिपोर्ट होती है जबकि पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने पर पीयूसी तैयार किए जाते हैं। पीयूसी में कर्मचारी की तैनाती से लेकर वर्तमान समय तक उसके सभी कार्य, आचरण, पदोन्नतियां आदि दर्ज रहती हैं।

बताते चलें कि बताते चलें कि जितिन शर्मा पर रेडक्रॉस सोसायटी के साठ हजार रुपये गबन करने का आरोप है। रेडक्रॉस सोयायटी की ओर से सितंबर 2020 में साठ हजार रुपये कीमत की दो रसीद बुक जारी की गईं थीं। आपदा प्रबंधन के एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए इन रसीदों को काट कर ये रुपये इकट्ठा करने थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया लेकिन जितिन ने वसूला गया धन सोसायटी में नहीं जमा करवाया। ऑडिट में उसकी ये चोरी पकड़ी गई। अधिकारियों ने ये मामला दबा दिया और सारे नियम ताक पर रख कर उसे पदोन्नति भी दे दी।

मज़दूर मोर्चा ने अंक 28 मई-3 जून में जितिन के इस गबन का फर्दाफाश किया तो उसे बचाने के लिए अधिकारी सक्रिय हो गए। आनन-फानन उसे सूचना दी गई और उसने 6 जून 2023 को शपथ पत्र बनवाया कि ये दोनों रसीद बुक उससे कहीं गुम हो गईं, और उसने इनमें से कोई रसीद नहीं काटी। इस संदर्भ में उसने थाना सेंट्रल मे रसीदें नहीं मिलने का रपट रोजनामचा दर्ज कराने का भी उल्लेख किया है। यह शपथपत्र उसने महासचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा को भेज कर उस पर लगे चार्ज समाप्त करने की गुहार लगाई है।

सच्चाई ये है कि जितिन शर्मा और अधिकारी रसीदें गुम होने की बात दबाए रहे और जब ऑडिट में ये गड़बड़ी पकड़ी गई तो बचने के लिए जितिन ने 12 फरवरी 2020 को सेंट्रल थाने में रपट रोजनामचा दर्ज कराया। सरकारी कार्य प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार कोई भी सरकारी दस्तावेज गुम होने पर संबंधित विभाग के कार्यकारी अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए न कि उस व्यक्ति द्वारा जिस पर गबन का आरोप है, ऐसा तो आरोपी को बचाने के लिए ही किया गया। रेड क्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों के कारनामे उनकी भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी कार्यशैली को दर्शा रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।